



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 96-2016/Ext.]CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016 (ASADHA 8, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 29 जून, 2016

संख्या 22/52/2005-5पी.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग, आदेश संख्या 22/52/2005-5 विद्युत, दिनांक 29 जुलाई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग, आदेश संख्या 22/52/2005-5 विद्युत, दिनांक 29 जुलाई, 2005 में पैरा 2, 2क तथा 2ख के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“2. प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैंप / ट्यूब लाइट्स अथवा ऊर्जा कुशल प्रकाश का अनिवार्य उपयोग:—

- सरकारी क्षेत्र / सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र / बोर्डों और हरियाणा के निगम या स्वायत्त निकायों द्वारा इन्कैंडेसेंट लैंप के उपयोग और नए सोडियम वाष्प लैंप और ऐसे लैम्प जिसकी दक्षता सोडियम वाष्प लैंप से कम है, की खरीद पर प्रतिबन्ध होगा।
- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैंप / ट्यूब लाइटों और ऊर्जा कुशल लाइटों (एलईडी से अधिक कुशल) का उपयोग निम्नलिखित सभी नये भवनों के लिए अनिवार्य होगा—
 - हरियाणा राज्य में स्थित केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संस्थाओं या प्रतिष्ठानों; तथा
 - औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं जिनका सम्बद्ध भार 30 किलोवाट या उससे ऊपर है।
- हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (हुडा) क्षेत्रों, नगरपालिका क्षेत्रों, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या उद्योग विभाग द्वारा विकसित क्षेत्रों में जहां पच्चीस से अधिक स्ट्रीट लाइटों के लिए एक ही स्विच स्थापित करना जरूरी हो वहां वर्तमान के साथ-साथ एवं नई स्ट्रीट लाइट पंक्तियों के लिए डस्क टू डॉन प्रचालन के लिए स्वचालित स्विचिंग प्रणाली (या तो सौलर या टाईमर आधारित) स्थापित करना अनिवार्य होगा।

पावर यूटिलिटीज इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो मास के भीतर प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैंप / ट्यूब लाइट्स या ऊर्जा कुशल लाइटों (एलईडी से अधिक कुशल) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए कनेक्शन और लोड जारी /स्वीकृत करते समय लोड मांग नोटिस में आवश्यक संशोधन प्रभावी होंगे।

प्रवर्ग 2(i) के अधीन विद्यमान भवनों के उपभोक्ताओं को सभी दोषपूर्ण पारंपरिक बल्ब, पारंपरिक ट्यूब लाइट, सी.एफ. एल. और टी-5 ट्यूब लाइट्स केवल एलईडी. लैंप / ट्यूब लाइट्स या ऊर्जा कुशल प्रकाश प्रणाली से बदलने होंगे।

प्रवर्ग 2 (ii) के अधीन उपभोक्ताओं को इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर उनके प्रतिष्ठानों में पारंपरिक बल्ब, पारंपरिक ट्यूब लाइटें, सी.एफ.एल. और टी-5 ट्यूब लाइट्स को प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल.ई.डी.) लैंप / ट्यूब लाइट्स या ऊर्जा कुशल प्रकाश प्रणाली से अपने स्वयं के खर्च पर बदलना होगा ।

टिप्पण :- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन राज्य नामित अभिकरण द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी, इन निर्देशों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इन निर्देशों की अनुपालना न करने की दशा में या निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा पर, पावर यूटिलिटीज को ऊपर वर्णित समय सीमा की समाप्ति के बाद, सम्यक् नोटिस के तामिल के बाद बिजली कनेक्शन काटने की शक्ति होगी। पावर यूटिलिटीज के कार्यकारी अभियंता (वितरण) इन निर्देशों का लागूकरण प्राधिकारी होगा और वे अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को इस संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजेगें।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Order

The 29th June, 2016

No. 22/52/2005-SP.— In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act 52 of 2001), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No. 22/52/05-5P, dated the 29th July, 2005, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No. 22/52/05-5P, dated 29th July, 2005, for para 2, 2A and 2B, the following para shall be substituted, namely:-

“2. Mandatory use of Light Emitting Diode (LED) lamps/ tube lights and energy efficient lighting:

1. The use of incandescent lamps and purchase of new sodium vapour lamps and lights having efficiency less than sodium vapour lamps by Government Sector/ Government Aided Sector/ Boards and Corporation or Autonomous bodies of Haryana is banned.
2. The use of Light Emitting Diode (LED) lamps/ tube lights and energy efficient lighting (More efficient than LED) shall be mandatory for all new:-
 - (i) Central or State Government Offices and Public Sector Undertaking Institutions or establishments located in the State of Haryana; and
 - (ii) Electricity Consumers in Industrial, Commercial and Institutional sectors having connected load of 30 kilowatt or above.
3. In Haryana Urban Development Authority (HUDA) Sectors, Municipal Areas, Areas developed by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (HSIIDC) or Industries Department, the installation of Automatic Switching System (either solar based or timer based) from dusk to dawn operation on existing as well as new Street Lighting Rows, where common switch for more than twenty five lights is required to be installed, shall be mandatory.

Power Utilities shall affect necessary modifications in the load demand notices within two months time from the date of issue of this order to promote the use of Light Emitting Diode (LED) lamps/ tube Lights or Energy Efficient Lighting (More efficient than LED) system while releasing or sanctioning new connections and loads.

The consumers of existing buildings under the category 2(i) shall replace all the defective conventional bulbs, conventional tube lights, CFLs and T-5 tube lights only by LED lamps / tube lights or energy efficient lighting system.

The consumers under the above category 2(ii) shall have to replace all conventional bulbs, conventional tube lights, CFLs and T-5 tube lights in their establishments with Light Emitting Diode (LED) lamps/ tube lights or energy efficient lighting system within one year from the date of notification, at their own cost.

Note:- The inspecting officer appointed by State Designated Agency under Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), may, therefore exercise power vested under the Act for the purpose of compliance of these directions. In case of non-compliance of these directions or on recommendation of Inspecting officer, the power Utilities shall have the power to disconnect the electricity connections after serving due notice after the expiry of the deadlines mentioned above. The Executive Engineer (Distribution) of the Power utilities shall be the enforcing authority of these directions and they shall send quarterly progress reports in this regard to the Renewable Energy Department, Haryana.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department.

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Order

The 29th June, 2016

No. 6/53/2008-1Lab 26366.— In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and in suppression of earlier notifications, the Governor of Haryana hereby appoints the Additional Labour Commissioner O/o Labour Commissioner, Haryana and the Deputy Labour Commissioners posted in the field offices in their respective areas of jurisdiction as Registering and Licensing Officers to exercise the concurrent powers of the Labour Commissioner as Registering Officer under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 for the entire State for the purpose of operation of the Single Window Services under one roof as per provision of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.

DR. MAHAVIR SINGH,
Principal Secretary to Government of Haryana
Labour Department.